



सियासत

राहत सामग्री की बंदर बाँट

कुछ लालची और मौकापरस्त लोगो के कब्जे में कई मजबूर व्यक्तियों लोगो का राशन

मानसरोवर के सेक्टर 123 की घटना, एक दूसरे पर लगाए आरोप

राहत सामग्री का क्रेडिट लेने की होड़ में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने

कोरोना संक्रमण की मार से जनता परेशान है। लॉकडाउन लगाकर जारी रहने से अब तो जनता के पास राशन भी खत्म होने लगा है। ऐसे में वे सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन यहां भी राजनीति ने पैर पसार लिए हैं। राशन सामग्री वितरण में अपने-अपने नाम के चक्कर में जनता परेशान हो रही है। मानसरोवर के सेक्टर 123 में शुकुवार को यही कुछ देखने को मिला। कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने हो गए।

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर, कोरोना वायरस के बीच गरीबों को राहत पहुंचाने में अब राजनीति आइं आने लगी है। शुकुवार को खंगानेर विधानसभा क्षेत्र के मानसरोवर इलाके में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। मानसरोवर के सेक्टर 123 में नगर निगम की टीम राशन बाँटने पहुंची तो जंटी लेने की होड़ में भाजपा-कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में पिड़ गए। पिड़ान में तीन-चार लोगो के मामूली चोट भी लगी। घटना के बाद भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कांग्रेसियों पर हमले का आरोप लगाया। वहीं, कांग्रेस से विधानसभा उम्मीदवार रहे पुष्पेंद्र शरद्वज ने विधायक लाहोटी और उनके कार्यकर्ताओं पर बौखलाहट की राजनीति करने के आरोप लगाए।



झगड़ में घायल लोग।

प्रशासन कर रहा भेदभाव
विधायक लाहोटी ने कहा कि प्रशासन की ओर से राशन वितरण में लगातार अनियमितता और भेदभाव किया जा रहा है। कलक्टर को भी अवगत करवाया, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने लोगों में ही इसका वितरण कर रहे हैं।



कैलेंडर हो घोषित

राहत सामग्री को जरूरत के खामान वितरण में अराजकता सामने आ रही है, उससे साफ है कि व्यवस्थाएं नाकाम हैं। राजनीति तो खैर खुलकर उजागर हो ही रही है। अफसरों व कर्मचारियों की फौज के बावजूद ऐसी समान गतिधारा और इलाके आहूते रहे गए हैं, जहां मदद नहीं पहुंच सकी है। क्या विषय के इस दौर में भी मुठ देखकर मदद पहुंचाई जा रही है? इससे तो आपस में विश्वास की डोर और भी कमजोर होगी। बोट की उम्मीद में मदद पहुंचने की कब्यद से बीमारी नहीं रुकने वाली। सरकार को चाहिए कि विधेति को नियंत्रण में लेकर क्षेत्रवार कैलेंडर घोषित करे कि कब और किस जगह मदद पहुंचेगी?

तीन बार बदली जा चुकी है व्यवस्था

शहर में खाद्य सामग्री वितरण की नहीं संभल रही व्यवस्था

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर, जयपुर में सूखी खाद्य सामग्री का वितरण जिला प्रशासन के लिए सिर दर्द बना हुआ है। अब तो अधिकारी इस जिम्मेदारी को लेने से ही बचने लगे हैं। जबकि खाद्य सामग्री से लेकर हर काम की पॉन्टिटरि को लेकर जयपुर में जिला प्रशासन के साथ 7 आइएस, 100 से अधिक आइएस और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी लगे हुए हैं। इसके बावजूद सभी जरूरतमंदों को अब तक खाद्य सामग्री नहीं पहुंच सकी है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते खाद्य सामग्री वितरण व्यवस्था को तीसरी बार बदलना पड़ा है।



प्रशासन कुछ बस्ती में राशन नहीं मिलने पर लोग घरने पर बैठ गए। लोगों की शिकायत है कि उन्हें राशन देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। विभिन्न संस्थाएं राशन लेकर आती हैं, जो परिषदों को देकर खले जाते हैं। लोगों ने कहा कि कई परिवारों के पास खाने का सामान नहीं है।

यों हो रही मुश्किल

केस -1: प्रताप नगर इलाके में लगभग 250 परिवारों के समूह राशन का संकट है। इनको प्रशासन से मदद अब तक नहीं पहुंच सकी है। लेकिन राजनीतिक विरोध के बाद इसे खाने सार पर शुरू करवाया गया। यह व्यवस्था भी सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस विधायकों के कहने पर अब वितरण निगम के जरिए करवाया जा रहा है। पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि किस क्षेत्रों में कार्यकर्ता चलेते को ही राशन बाँट रहे हैं। शहर आठ विधानसभा क्षेत्रों में बाँटा है और प्रत्येक में 15 हजार जरूरतमंद बताए जा रहे हैं।

मिसाल

करनाल के मांडल की सराहना

खाद्य सामग्री वितरण को लेकर हरियाणा के करनाल मांडल की प्रशंसा हो रही है। करनाल में एडोप्ट ए फैमली कंसेंट के राहत लेगों को घर-घर राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके जरिए अब तक 1.5 हजार परिवारों की मदद की जा चुकी है। यहां प्रशासन ने नगर निगम के जरिए विक्सस समितियों को साहू लेकर इलाके में जरूरतमंदों की सूची तैयार करवाई और समितियों के जरिए ही राशन वितरण का काम शुरू किया।

कई बार चेताने के बावजूद राजनैतिक व्यक्तियों की मौकापरस्ती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी तक तो सत्तारूढ़ पार्टी के जन प्रतिनिधि कानून को धत्ता बताते हुए कर्फ्यू का खुलेआम उल्लंघन कर, खुद ही राहत सामग्री बाँट रहे थे। परन्तु अब तो हद ही हो गयी लगता है। अब तो सत्तारूढ़ और प्रमुख विपक्षी पार्टियों में राहत सामग्री की बंदर बाँट को लेकर सिर फुटव्वल की नौबत तक आ चुकी है। ऐसी ही एक घटना में सांगानेर विधानसभा के विधायक अशोक लाहोटी

और यही से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार पुष्पेन्द्र भारद्वाज के कार्यकर्ताओं के बीच राहत सामग्री के वितरण को लेकर हाथापाई तक हो गयी। परन्तु सरकार है कि इन लोगो के विरुद्ध कोई सख्त कदम नहीं उठाकर इन लोगो के गैरकानूनी क्रत्यों को बढ़ावा दे रही है।

प्रशासन की नाकामी

इन सब घटनाओं से स्थानीय प्रशासन की नाकामी साफ़ नजर आती है, यह हालात तो तब है जबकि यह खुद राजधानी क्षेत्र है

और सरकार के सभी बड़े नुमायिंदे यही बैठते हैं। सरकार ने अपने कई आला अधिकारियों को जयपुर में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लगाया हुआ है। परन्तु इसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन के कामों में राजनैतिक दखलंदाजी साफ़ देखी जा सकती है।

कर्फ्यू में भीड़ जुटाने की शिकायत

जयपुर @ पत्रिका. कोतवाली थाने में विधायक अमीन कागजी और अन्य लोगों के खिलाफ कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भीड़ जुटाने की शिकायत दी गई है। मालवीय नगर निवासी एडवोकेट पूनमचंद भंडारी ने यह शिकायत दी। उन्होंने नमक की मंडी में कर्फ्यू लगने के बावजूद राशन बांटने पहुंचे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। थानाधिकारी यशवंत सिंह ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। शिकायतकर्ता को दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है।

श्री पूनमचंद भंडारी का साधुवाद

स्थानीय विधायक अमीन कागजी द्वारा कर्फ्यू का उल्लंघन कर अपने लोगो को राहत सामग्री बांटने के विरुद्ध स्थानीय एडवोकेट श्री पूनम चंद भंडारी द्वारा कोतवाली पुलिस को शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग की गयी है।

सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्रियों कर कब्जा किया। अपने लोगो के घर भर दिए, जबकि मजबूर लोगो तक नहीं पहुंच रही राहत सामग्री।

सामने आया है कि सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहत सामग्रियों पर कब्जा कर लिया है और यह लोग खुद के और अन्य चापलूस, मुहलगे कार्यकर्ताओं के घर

भरने में लगे हुए हैं। यही नहीं, वायरल हो रहे मेसेजों के अनुसार यह लोग इन राहत सामग्रियों के बदले दुकानदारों ने अन्य चीजों का मोलभाव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी और शहर के बाहरी इलाकों में वास्तविक जरूरतमंद लोगो के पास यह राहत सामग्री पहुंच ही नहीं पा रही है। यह लोग स्थानीय निवासियों की सहायता से ही इस कठिन समय को काटने को मजबूर हैं।

कैसे लड़ेंगे कोरोना से?

इस कठिन समय में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि जरूरतमंद लोगो तक उनकी आवश्यकता के अनुसार सुखी या तैयार भोजन व्यवस्था की जाए और यह काम सरकारी तंत्र से ही बखूबी कराया जा सकता है क्योंकि इन कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। इसके लिये जरूरी है कि निर्वाचन व्यवस्था में लगे लोगो की सेवाएं ली जाये क्योंकि यही तंत्र है जिसकी पकड़ हर परिवार और हर व्यक्ति तक होती है। BLO से बेहतर यह काम कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है जरूरी है कि स्थानीय BLO के नेतृत्व में ही टीम बनाकर राहत सामग्री का वितरण किया जाये।